SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Sir, it is our business to know why what are the grounds of her resignation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : She has just resigned.

SHRI MAHAVIR TYAGI: A Joint Committee is the responsibility of both the Houses. We have both selected Members and if there is any resignation we must know the reasons for it.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : May I clarify? Shrimati Parvathi Krishnan happened to be on two important Committees along with some other Members. According to the decision of our Party she has resigned because we do not think that one Member should be on too many Committees since it is difficult to discharge their responsibilities. Therefore, in the interest of Parliamentary work she has taken upon herself the responsibility of one of the Committees and resigned from the other.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House do recommend to Lok Sabha that Lok Sabha do appoint a member of Lok Sabha to the Joint Committee of the Houses on the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 1973 in the vacancy caused by the resignation of Shrimati Parvathi Krishnan from the membership of the said Joint Committee and communicate to this House the name of the member so appointed by Lok Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

THE ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) AMENDMENT BILL, 1974

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974, be taken into consideration."

As the hon'ble House is already aware, by the Esso (Acquisitions of Undertakings in India) Act, 1974, rights, title and interests of Esso Eastern Inc. in relation to its undertakings in India were acquired by the Central Government. Section 13 of that Act provided that every contract entered into by Esso Eastern Inc. for any service, sale or supply in India shall unless terminated by the Central Government within 180 days from the 13th March, 1974 *i.e.* on the 8th September, 1974, be binding on the Central Government or the Government Company to which the said undertakings may be transferred. That section also specifies the procedure for the termination of such contracts. In view of the very complex and diverse nature of these contracts and their large number, it has not been possible to complete the work of scrutiny of all the contracts undertaken or such further action as is appropriate within the specified limit of 180 days. As such, it has, therefore, become necessary to extend the period by a further period of six months so that the total period available for the scrutiny and termination of contracts may be made one year. I would, therefore, strongly commend this Bill for adoption by the hon. House.

The question was proposed.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : श्रीमन्, अभी जो विधेयक पेश किया गया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू। उसका मैं विरोध करता हूं तीन-चार कारणों से। बहुत दिन नहीं बीते कि इस मंत्रालय की ओर से एस्सो कंपनी को लेने का बिल पेश किया गया था और सदन ने इसको पारित किया था। जब पारित किया था तो सदन के फैसले के मुताबिक सरकार का यह कर्तव्य था कि 6 महीने के भीतर एस्सो कंपनी की सर्विसेज, सप्लाई और सेल के जितने भी कान्ट्रैक्ट्स हैं उन तमाम काट्रैक्ट्स की छानबीन करके उनमें जो भी राष्ट्रीय विरोधी हैं, हमारे देश के

हित के खिलाफ हैं उनको खत्म करके इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह पार्लियामैंट का मैनडेट था और यह मैनडेट था गवर्नमैंट ने जो बिल पेश किया था उसके आधार पर। आज ये मंत्री महोदय सदन में आते हैं यह कहने के लिए कि इस मैनडेट को पास कर दो। आप जब यह कहते हैं कि इसको 6 महीने से बढ़ा कर साल भर कर दो तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि 6 महीने के भीतर इन तमाम कांट्रैक्ट्स की छानबीन करके इस सिल-मिले के अदर अन्तिम फैसला ले नही पाए थे। यह पार्लियामैंट का मैनडेट था और आपने इस मैनडेट को पूरा नही किया। चूंकि पार्लियामैंट के इस मैनडेट को आपने पूरा नही किया इसलिए आप की निन्दा होनी चाहिए न कि आपके इस विधेयक का समर्थन होना चाहिए।

दूसरी चीज मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इन विदेशी कंपनियों के मामले में जिस तरह से सरकार दीर्घ सूत्री का सिलसिला चलाए हुए है—मै इस बारे में एक संस्कृत की कहावत सुनाना चाहता हू :—

"दीर्घ सूत्री विनशयति"

जो दीर्घ सूत्री की नीति चलाता ह उस नीति को चलाने वाला नष्ट हो जाता है। यह हमारे हजारों वर्ष का अनुभव है। यह विदेशी कंपनी कोई साधारण विदेशी कंपनी नहीं है। दुनिया की सैवन सिस्टर्स इन्टरनेशनल मेजर आयल कंपनी है और दुनिया भर मे हुकूमत करने वाली है। उनके साथ इस तरह का ढीलापन आप चला रहे हैं बावजूद इसके कि पार्लियामेंट का यह निश्चय था कि 6 महीने के भीतर आप को यह सब काम कर लेना चाहिए। एक तरफ इस देरी का नतीजा यह हो रहा है कि सेल द्वारा सर्विसेज के द्वारा और सप्लाई के द्वारा हमारा शासन विदेशी कंपनी चला रही है और दूसरी तरफ उसकी मियाद आप 6 महीने और बढ़वा रहे हैं। हम नहीं समझते है कि इस देश की पार्लियामेन्ट इन विदेशी कम्पनियों की अवधि बढ़ाने के लिए राजी हो क्योंकि यह भारतीय जनता की पार्लियामेन्ट है, इन्टरनेशनल सेवनसिस्टर्स आफ आयल कम्पनीज की पार्लियामेन्ट नहीं है। तीसरी चीज यह है कि जिस तरह से समय को बढ़ाया जा रहा है, छः महीने से एक साल किया जा रहा है, इसका नतीजा यह भी होगा कि बाकी दूसरी दो विदेशी तेल कम्पनिया, जिनके राष्ट्रीय-करण की नीति सरकार मान चुकी है, उनके राष्ट्रीयकरण का मामला भी टल जाएगा और उनके राष्ट्रीयकरण की अवधि बढ़ जाएगी। पता नही इनके शासनकाल में यह भी हो सकेगा या नही। लेकिन इसका नतीजा यह अवश्य होगा कि विदेशी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की जो नीति अपनाई गई है वह घपले में पड़ जाएगी, उस पर अमल नही होगा और आजकल तो सरकार का मल्टी नेशनल कम्पनीज के साथ जिस प्रकार से प्रेम का सिलसिला चल पड़ा है उसको देखते हुए हमें बहुत सारे खतरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन तीन कारणों से हम इस बिल का विरोध करते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान): उपाध्यक्ष जी, वैसे तो यह विधेयक

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

बहुत साधारण है। सरकार ने जुलाई मास में इस कम्पनी की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी और इस थोड़े समय के अन्दर सरकार का यह कहना है कि वह सारे कांट्रेक्ट को स्टेडी नहीं कर पाई है। इस कारण से छ. महीने की जो एपाइन्टेड डेट थी, वह समय समाप्त होने के बाद छः महीने का समय और दिये जाने के लिए कहा गया है। मैं समझता हू कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत साधारण बात है। सरकार ने स्वयं माना है कि काट्रेक्ट कुछ इस प्रकार के कामप्लेक्स और डाइवर्स नेचर के हैं कि उनके कारण दिक्कते भी आ सकती हैं। लेकिन अगर सरकार या मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण देते कि इन काट्रेक्ट के बढ़ाने की जो बात की जा रही है फाइनेलाइजेशन की दृष्टि से, उसमें क्या आर्थिक बोझ और आने वाले है और सरकार कम्पनी के जो शेयर खरीदना चाहती है उसके लिए कितना कम्पेंशेसन देना पड़ रहा है और यह कम्पनी अपनी सर्विस के लेहाज से और अन्य सारी चीजों के एवज में जो चीजें बाहर भेजती है, उसके कारण से कितना आर्थिक बोझ इस देश पर पड़ने वाला है, जब तक सरकार इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं देती है तब तक मुझे लगता है कि जैसी आशंका मेरे पूर्व वक्ता सदस्य महोदय ने व्यक्त की है कि इस विदेशी कम्पनी के साथ सरकार ने जिस प्रकार की सौदेबाजी की थी, उससे देश को हानि ही उठानी पड़ेगी। मुझे यह भी लगता है कि अवधि बढ़ाने से देश को हानि ही होगी। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सन् 1972 से एस्सो कम्पनी को लेने की बात चल रही थी और जिस प्रकार से टर्म्स एण्ड कन्डीशन की बात चली और जिस प्रकार से नेगोशिएशन चला उसमें दो साल चले गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देरी के कारण से इस कम्पनी को सरकार को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े? सरकार ने 74 परसेन्ट शेयर लिये हैं और वे मार्किट प्राइस पर लिये है। ये क्यों लिये? इसका कारण यह है कि पिछले दिनों के अन्दर धीरे-धीरे सरकार ने अवधि बढ़ाई और यह कहा कि सरकार शेयर खरीद रही है, इसके कारण शेयरों के दाम बढ़ गये। मैं पूछना चाहता हू कि सन् 1971-72-73 और सन् 1974 में शेयरों की मार्किट प्राइस क्या थी? अगर सरकार 1971 में यह काम कर लेती तो उससे कितना अन्तर पड़ता यह देखने की बात है। मुझे लगता है कि सरकार को अधिक पैसे देने पड़े। इसलिए मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो अवधि फाइनेलाइजेशन के बारे में बढ़ाई जा रही है उससे हमारे देश को आर्थिक नुकसान होगा।

एक बात तेल के सबंध में आई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस एस्सो कम्पनी की व्यवस्था को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन की व्यवस्था से अलग क्यों बनाना चाहती है? इंडियन आयल कारपोरेशन हमारे पास है, ओ० एन० जी० सी० हमारे पास है। क्या यह काम इंडियन आयल कारपोरेशन नहीं कर सकती है? सरकार कहेगी कि इसकी व्यवस्था अलग है, इंडियन आयल कारपोरेशन तो एक सरकारी

संस्थान है, इसकी और उसकी व्यवस्था में अन्तर है। पिछले दिनों में यहां पर चर्चा चली कि हम साबुन के दाम बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। यह बात एक सवाल के जवाब में कही गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में साबुन के दाम बढ़ गये। इसलिए यह सवाल पैदा होता है कि बाकी जो कम्पनिया है उनके बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है?

आप उनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, सरकार का कोई फर्म डिसीज़न होना चाहिए उनके बारे में। बार बार यह चर्चा चल रही है कि बर्मा शेल को भी हम लेंगे, कालटेक्स को भी हम लेंगे—लेने का विचार कर रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है। इस प्रकार की चर्चा चलाना उपसभापति महोदय, बहुत हानिकारक है और जैसा मैंने कहा, इस कंपनी की भी चर्चा जो 1972 से चलाई उसके कारण शेयर का जो वैल्यू बढ़ा उससे सरकार को ज्यादा धन देना पड़ा। इसके बारे में मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि सरकार की क्या नीति है, सरकार उन कंपनियों को लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है और यदि लेना चाहती है तो तुरंत इस बारे में घोषणा करके उन कंपनियों को लेने में कौन सी दिक्कत और बाधा आ रही है? तो उसको भी सदन के सामने रखना चाहिए था और हमारी यह मांग किसी पार्टी के आधार पर नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने भी मांग की है और मैं भी मांग करता हूं कि बाकी जो विदेशी तेल कंपनियां हैं, देश का शोषण करने वाली, अगर आज उनको पूरे रूप में नहीं लिया तो मै चाहता हूं कि उनका भी भारतीयकरण कर देना चाहिए। उनको सरकार द्वारा कंपेन्सेशन देने के दृष्टिकोण के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इकानामिक टाइम्स ने इस्टीमेट किया था कंपेन्सेशन के बारे मे कि 12.42 करोड़ रु० उनको कंपेन्सेशन देना चाहिए लेकिन मुझे पता लगा कि सरकार उनको लगभग 20 करोड रु० कंपेन्सेशन दे रही है। यह एस्सो कंपनी को कंपेन्सेशन ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? और क्या इस बात की जो चर्चा चली है पिछले दिनों कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, उनके कांग्रेस पार्टी से अच्छे संबंध हैं और यह कंपेन्सेशन इसलिए बढ़ा है कि ब्लैक मनी में कांग्रेस पार्टि का शेयर है, इसलिए एस्सो कंपनी को 12.42 करोड़ रु० का जो इकानामिक टाइम्स ने कंपेन्सेशन के बारे में मेन्शन किया है उसकी बजाए 20 करोड़ रु० दे रहे हैं, तो इस प्रकार कंपेन्सेशन बढ़ाने का क्या कारण है? जब तक इन सारी बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, क्योंकि यह समय बढ़ाने जैसी साधारण बात नहीं लगती है इसलिए कि इसमें बड़े कांप्लेस और डाइवर्स कांट्रेक्ट्स हैं और जिस प्रकार की हालत, जिस प्रकार की व्यवस्था पिछले दिनों रही, जिस प्रकार की नीयत रही है, उससे देश को जिस प्रकार नुकसान हुआ है, उसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैं समझता हूं यह जो विधेयक रखा है इससे देश के हितों का नुकसान होगा और इसलिए इस विधेयक का विरोध होना चाहिए।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Sir, I oppose this amendment Bill because it is absolutely counter to the interests of this country. The original Bill itself was like that. This 26 per cent share of the original company was specially devised to give them greater power on all important decisions. The Hindustan Petroleum Corporation or Company is only in name. Sir, the Minister is not listening. An hon. Member is talking to him. What does he know about oil or oil products?

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : I object. He is a big farmer. He uses lot of oil; besides he knows how to oil the Minister.

SHRI NIREN GHOSH : Very good comment. I need no object to it.

Sir, I was saying that this 26 per cent equity share participation is very dangerous. It is a dead blow to the interests of India. I again say that the Petroleum Ministry under Dr. Triguna Sen had recommended 100 per cent nationalisation. I have repeated it several times. Nobody has cared to rebut it. So it stands. In the interests of foreign oil companies, the special device was incorporated. We are told that there is some agreement with the foreign company that they can import crude from the parent company. I say it is wrong, false and a lie. There is no such written agreement. This particular thing you have bestowed upon the foreign oil company in order to help them send about two hundred to three hundred crores of rupees which they can send out from India and they have done it and this process will still continue and it is because of this 26% equity share that you have allowed. Because of this they will continue to import and, Sir since January, though there has been no rise in the OPEC prices, there have been several hikes in the price of the imported crude of these foreign oil companies and you are continuing to do that. Even Mr. Borooah, your senior colleague, admitted it the other day on the floor of this house. The price hikes have been done several times and, Sir, you will be surprised to hear that since this agreement and since other agreements like this are going to be entered into with the other oil companies this Burmah-Shell has removed crores of rupees worth of immovable property wholesale and now the loot is taking place. I charge this Government with allowing Burmah-Shell to take away crores of rupees' worth of immovable property. I have received telegrams from the Petroleum Workers' Union. I told this here only the other day and I repeat it here now and you are continuing with this. Not only that. In Tamil Nadu, the entire transport, the truck transport, etc. will be given to this company for the transport of oil and they will do it on a contract basis and earn a lot on this score also. This is what is happening. You will be surprised to learn, Sir, that since 15-7-74, because of this 26% which the Government has allowed them, the money has gone to their coffers, not to the Government by way of the extra Excise duty which it imposed. Apart from that, the rates are now like this: On diesel, it is Rs. 30 per kilolitre, on kerosene Rs. 30 per kilolitre, on LDO it is Rs. 50 per kilolitre and on furnace oil it is Rs. 38 per kilolitre. Now, they are going to make the inventories and all other necessary adjustments. It may take about six months or so and in the mean time they have taken several crores: another six months will be there and they will take several crores more. So, are you the Government of India or are you the servant of Esso? Let us be clear about it and let there be no hide-and-seek game about it. So, this is what it has come down to. There has been collusion on the naphtha business and I do not want to go into the details. The other day it was alleged that there was some shady deal with the industrialists and several crores of rupees have gone to the Congress funds. Yes, it was alleged like this and nothing has been done so far to refute it. You come and say, "I refute it". That will not serve the purpose.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh, you also come and make some allegations. So, somebody must refute them also.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : You just make the allegations and we also have to refute them.

SHRI NIREN GHOSH : Sometimes I give the correct figures and facts. Yesterday, Sir, I gave certain figures, certain facts, and...

SHRI BHUPESH GUPTA : What is about?

SHRI NIREN GHOSH : ....they have not come forward to refute them. All the VIPs are involved, very big people are involved including the Prime Minister. Mr. Bhupesh Gupta, your socialist friend, Shri Malaviya, the Prime Minister, Air Marshal Arjan Singh, the industrialist Shri Bharat Ram—all these people are involved.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh, you not come to the subject.

SHRI NIREN GHOSH : So, what I say is that I sometimes give and I have given the correct facts and figures. The unfortunate part of it is that the Government has to decide about all these things.

Now I am telling you that you take over this company. There should be no 26% business. It should be hundred per cent. The best thing would be to take over the management. Don't pay them a single pie. Take the management in perpetuity. Whatever the profits, you utilize them for the growth of the oil industry in India so that not a single dollar has to be paid.

You have mismanaged excess capacity. Another point is that excess capacity had been regularised at 2.70 million. Now it has been extended; further excess capacity is being granted in the guise of H.P.C., Hindustan Petroleum Company. But actually what does it mean? So many million tonnes of crude they will import. Everybody knows that the cost of production of a single barrel of crude is only 25 cents; they are charging eleven dollars. These are the profits that are being distributed between the producing companies It is not because of the producing companies. They charge the internationa price. They are earning super and super profits; and by this back door you are doing this, you are extending it to 3.5 million tonnes from 2.7 million tonnes.

Lastly, I will put you a question. This is a serious question. Petrol and petroleum products are the basic ingredients of an industry. Why should not there be an equalization of petrol and petroleum products throughout India, which are essential ingredients of industry? Without steel and coal, industry cannot run. You talk of a balanced and proportional and equitable development of all the regions, of all the States, in India. You have come under the monopolists based in the western coast of India. This is a horrible thing. So I demand a categorical answer to my question : Why should there not be equalization of petrol and petroleum product prices throughout, which are essential ingredients of industry. If you do not accept that, then you must satisfy us and give reasons for this.

With these words, I conclude.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभापति जी, विधेयक बहुत साधारण है और मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साधारण सी बात में भी नीरेन घोष जी को राजनीति दिखाई देती है. . . .

SHRI NIREN GHOSH : You know something of Haryana bull, and ..

श्री रणबीर सिंह : इन भाइयों को हर चीज में राजनीति के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता।

SHRI NIREN GHOSH : ..and being a *kulak* farmer, what do you know about oil?

SHRI RANBIR SINGH : I consume oil, my friend.. (*Interruptions*)

SHRI NIREN GHOSH : You get it cheaper than the rate at which one gets in Tamil Nadu or in Orissa or in Andhra. You want your pound of flesh. You are selfish...

श्री रणबीर सिंह : अगर मैं चाहूं तो आपको ओवर-ओ कर सकता हूं, लेकिन यह कुछ अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह

[श्री रणबीर सिंह]

से जो कड़वी बात आप कहते हैं, शांति से हमने सुना, आप भी साहस करें। जो तथ्य है, सच्चाई है वह तो शांति से सुनें। हो सकता है कि उसमें आपकी सोच में फर्क आए। उप-सभापति जी, इस देश के अंदर यह सरकार है या आम देश वासी हों या किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हों या इस सदन के सदस्य हों, कोई यह नहीं चाहता कि इस देश के अंदर तेल के या दूसरे कोई कारखाने विदेश के सरमायेदार चलायें। लेकिन देश की मजबूरियां हैं। देश की तरक्की जिस तरीके से होती है, जिन मुश्किलात से उसे गुजरना होता है उस को हमें देखना पड़ता है। मुझे याद है अगर हम पिछले दस, पंद्रह या बीस वर्ष के आर्थिक इतिहास को देखें तो पता लगेगा कि यह विरोधी दल वाले सदस्य क्या-क्या विचार रखते थे। अभी नीरेन घोष जी ने कहा था कि लोहा, कोयला और तेल बहुत जरूरी है देश के अंदर कारखाने चलाने के लिए और इस बात में कोई दो राये नहीं हो सकती और इस बात से भी वह इन्कार नहीं कर सकते चाहे वह कितना ही चिल्ला कर इस सदन में कहें या कितना ही बात को तोड़ मरोड़ कर बाहर कहें, इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि इस देश में एक समय था कि जब लोहा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही पैदा होता था। आज लोहा देश के सरकारी क्षेत्र में पैदा होता है। सिर्फ एक टिस्को ऐसा कारखाना है जिस में दोनों की साझेदारी है, वरना जितना लोहा पैदा होता है वह सब सरकारी क्षेत्र में पैदा होता है। मुझे याद है कि जब तमाम सारे विरोधी दल के सदस्य जिस तरह से आज नीरेन घोष जी कांग्रेस पार्टी को दोष लगा रहे थे कि चोरी के रुपए में उन का हिस्सा है, उसी तरह से वह सदस्य पहले कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी सरमायेदारों से दबी हुई है और यह कभी लोहे के कारखानों का सरकारीकरण नहीं करेगी। जब कोयले का सवाल आया तो यह कहा करते थे कि कोयले की खानों के जो मालिक हैं उन से कांग्रेस पार्टी पैसा लेती है और उन का सरकारीकरण कभी नहीं होगा। लेकिन लोहे का हुआ और कोयले का हुआ और तेल के सरकारी-करण की तरफ हम जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम शायद विदेशी कंपनियों से पैसा कमाते हैं और जब नीरेन घोष जी बोल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं किन-किन आदमियों, अधिकारियों और सदस्यों का उन्होंने जिक्र किया, मैं ने उस समय कहा था, शायद उन्होंने सुना न हो कि आप के हिसाब से तो भगवान का भी उस में हिस्सा है, उस चोरी में। वह उन का एक सोच है और वह इस सोच के शिकार हैं। उस में उन का कोई कसूर नहीं है। जो चश्मा उन को लगा है उस से देश की तरक्की उन को दिखायी नहीं देती। उस में सिर्फ उन को सरमाये-दारों का रुपया और लूट का रुपया ही उन को दिखायी देता है। कांग्रेस यह खा गयी, फला यह खा गया, इस के अलावा उन को कोई दूसरा विचार आता नहीं। देश की तरक्की कैसे हो इस को वह सोच नहीं पाते। वरना अगर इस बात को वह सोच सकते तो इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह देश वह देश था जिस में आज से कुछ साल पहले जितने कारखाने थे,

जितना रुपया उन में लगा था वह सारा निजी क्षेत्र का रुपया था और आज इस देश के अंदर बावजूद इस बात के कि कुछ भाई कहते हैं कि हम सरमायेदारों से काला धन लेते हैं और इसलिए उन से दब रहे हैं, लेकिन यह एक तथ्य है कि आज देश के कारखानों में जितना रुपया लगा है उस में 29 सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा सरकारी क्षेत्र के कारखानों में लगा है और सिर्फ 23 सौ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र के कारखानों में लगा है। हमारे देश के अंदर हमारी नीयत बिलकुल साफ है। माथुर साहब चाहते थे कि सरकार ऐलान करे। सरकार ने आज से नहीं कई साल पहले से ही ऐलान किया था कि इस देश के अंदर हम एक आर्थिक ढांचा, समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं और एक नया सामाजिक ढांचा कायम करना चाहते हैं और उस की तरफ सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। हम यह जानते हैं कि उस में मुश्किलात हैं। आप जानते हैं कि रेल तो सारी सरकारी है और रेल के पहिये को जाम करने के लिए यह सारे विरोधी दल के सदस्य अलिफ से ले कर ये तक, लगे हुए थे और यह लोग उस समय निजी और सरकारी क्षेत्र की जो लड़ाई है उस को भूल गये। तो सरकार के मंत्री को या किसी दूसरे आदमी को उकसाना आसान काम है। श्रीमन्, मैं क्या पूछ सकता हूं श्री नीरेन घोष जी से कि जिन देशों में सरकारी क्षेत्र से काम चलता है, कारखाने चलते हैं क्या वहां नीरेन घोष जी जैसे सदस्य हैं कि जो स्ट्राइक की बातें करते हैं? ऐसी कोई बात क्या वहां है? वह है नहीं। तो आज हमारे देश के अंदर क्योंकि देश में प्रजातंत्र है, सब को सारी स्वतंत्रता है। यहां सब की जबान खुली हुई है। कोई भी सही बात भी कह सकता है और गलत बात भी कह सकता है और उस सब को देखा जाता है।

इसलिए एक सही बात होती जा रही है उसमें से बुटियां निकाली जाती हैं। कौन रुपया देना चाहता है विदेश की कंपनियों को? एक पैसा भी कोई नहीं देना चाहता है। लेकिन सही बात देखनी चाहिए।

आज तेल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हो गया। खेत की पैदावार के लिए जरूरी हो गया। तेल कारखाने की पैदावार के लिए जरूरी हो गया। एक समय था जहां-जहां तेल पैदा होता था ताकतवर देश इसके ऊपर इसलिए कब्जा रखना चाहते थे कि लड़ाई में इसकी बड़ी जरूरत होती है। लेकिन आज तो लड़ाई नहीं रोजाना के जीवन में तेल का इतना ऊंचा स्थान हो गया कि चाहे वह खेती है, वह कारखाना है, वह चल नहीं सकता जब तक कि तेल न मिले। आप चाहते हैं कि जो ढांचा है उसको एकदम से तोड़ दिया जाए। उस तोड़े हुए ढांचे के अन्दर कितनों को क्या तकलीफ होगी यह बात ए सोच की बात है। हो सकता है कि कुछ थोड़े समय में, 6 महीने में उनको जो मुनाफा मिलता है थोड़ा और मुनाफा वह ले जाये। लेकिन उसके मुकाबले में देखना यह है कि अगर इस ढांचे में कोई गडबड हो तो कितना कुछ नुकसान देश को हो सकता है। यह तो कंपेरेटिव पोजीशन को देखने वाली बात है कि अगर पहले से तो हमें कितना फायदा है और कुछ गडबड़ी हो तो कितना

[श्री रणबीर सिंह]

नुकसान है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, एक तरफ जम्मू-काश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसका शांति से ट्रांसफर नहीं हुआ वह लड़ाई से हुआ उसके ऊपर कितना खर्च हुआ और बाकी स्टेट्स के राजाओं को वजीफा देकर जो रजवाड़े थे उनको लिया गया। वह कितना महंगा पड़ा और जो लड़ाई से लिया वह कितना महंगा पड़ा। उनका वजीफा भी बन्द हो गया।

आप जो समझते है कि विदेशी कंपनियों की तरफ कदम नहीं उठायेंगे तो विदेशी कंपनियों का सरमाया यहां रहने वाला नहीं है। लेकिन देश के कारखानों के लिए जब तक विदेशी सरमाये की आवश्यकता है, सरकार को लेनी होगी। वह हमारे देश ने ही नहीं लिया, रूस ने लिया, चीन ने लिया। रूस भी विदेशों से अनाज लेता है, चीन भी लेता है, विदेशी सरमाया भी लेता है अपने देश की तरक्की के लिए। तो हमारी सरकार कोई कुसूर नही करती। इस देश के खिलाफ कोई जुर्म नही करती। अगर देश की तरक्की के लिए विदेशी सरमायेदारों को बढ़ावा देना पड़ता है, कोई नहीं चाहता कि विदेशी सरमाया हम लें, कोई नही चाहता कि निजी क्षेत्र के साहूकार हिन्दुस्तान के अवाम को लूटें, लेकिन एक मजबूरी है। उनको कुछ छूट देनी होती है और यही हमारे देश का आर्थिक इतिहास है। कुछ भाई जो उधर की बैंचों मे हैं उनको इस बात का फिक्र नही है कि अगर कहीं थोड़ा ढांचे मे गड़बड़ हो जाए तो उसमे कितना नुकसान होगा।

आप जानते हैं कि इस साल बारिश कई स्थानों पर नही हुई, कम हुई खेत की पैदावार में कमी आई। आज देश के अन्दर कितनी महंगाई दिखाई देती है। तो तेल की कमी की वजह से इस देश के अन्दर आर्थिक ढांचे में कितना उथल-पुथल हो सकता है उसका नुकसान कितना हो सकता है उसकी तरफ ध्यान नहीं। 12 करोड़ की तरफ है, 50 लाख की तरफ है। इसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। लेकिन तेल में टोटा नफा दोनों समझकर करें तभी सही होगा। एक चश्मा लगाकर नीरेन बाबू जो कहते है, उससे देश आगे बढ़ने वाला नही है। तो मै निवेदन करूंगा कि यह साधारण सा बिल है, 6 महीने हम इसकी मियाद को न बढ़ायें तो जो पहले फैसले हुए हैं वह भी गडबड़ मे फस सकते है। तो इससे किसको फायदा होने वाला है? विदेशी कंपनियों को या हमारे देश को, यह सोचने की बात है। उसके अन्दर कितना घाटा नफा हो सकता है। घाटा हो तो कितना घाटा हो सकता है, अगर न करें तो कितना नुकसान हो सकता है। ये तो हर चीज में कहते है, हर चीज में इनको कांग्रेस का पैसा दिखाई देता है। कांग्रेस से आप हार गये, यह देश जानता है। उस हार को आप भूल नहीं सकते। उस हार का भूत बार-बार आपके सामने आयेगा, वह हट नहीं सकता है। आपको उसको भूलना होगा और समझ से बात करनी होगी और सही चीज दिमाग पर उतरेगी तभी समझ में आयेगा।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी रणबीर सिंह का जवाब दे रहा हूं। सरकार का

कोई दोष नहीं है, उसकी नीतियों का कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ इस बात का है कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया। न उसका सरकारी मशीनरी पर विश्वास है, न उसका नेताओं पर विश्वास है। यह देश का दुर्भाग्य है कि 27 सालों के अन्दर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हम धीरे-धीरे विश्वास मे खोते चले गए। वह बहुत बड़ा दुरदिन होगा जब विश्वास इस हद तक खो जाएगा कि जनता अपने नुमाइन्दों पर से भी विश्वास खो बैठेगी। जब इसमें तेजी आ जाएगी तो इस देश का भविष्य भी अन्धकारमय हो जाएगा।

जो भी चीज आप हाथ मे लेते है उसका राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण हो जाता है और सरकारीकरण के नाम से जनता को इतनी चिढ़ हो गई है, सरकारी-कर्मचारियों पर इतना अविश्वास हो गया है कि जो भी काम सरकार हाथ में लेती है--चाहे अच्छे से अच्छा काम क्यों न हो--और उसको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी मशीनरी आगे बढ़ती है तो जनता यह समझती है कि यह काम बिल्कुल बाहियात हो गया है। पूंजीपतियों मे उसको घबराहट हो गई है, प्राइवेट इन्टरप्राइज मे भी उसको घबराहट हो गई है। इसलिए इस बात को छिपाया नहीं जा सकता कि हमारी व्यवस्थाएं ढीली से और बर्बादी की तरफ जा रही हैं।

एक तरफ हम सारी चीजें सरकार के हाथ में देने की कोशिश कर रहे है और दूसरी तरफ--मैं आपको यू० पी० की मिसाल देना चाहता हूं--आप जानते हैं कि यू० पी० में बिजली के कारखाने सरकार ने अपने हाथ मे लिए और अब वे सब बेचे जा रहे है। एक बार यू०पी० सरकार ने सारी बसो को अपने हाथ मे लिया लोगों ने समझा अच्छा इन्तजाम होगा लेकिन खराब हो गया। बसें और खराब हो गई, किराए बढ़ा दिए गए और अब उसको सरकार कारपोरेशन को दे रही है। अपनी अक्षमता जाहिर कर रही है।

आप 6 महीने से साल भर का समय चाहते है कोई बेजा नहीं है। आप काम पूरा नहीं कर सके कोई बात नहीं लेकिन क्यों नही कर सके सवाल इसका होना है। जिस समय आपने इस मसले को तय किया तो आपने सोचा होगा कि 6 महीने के अंदर हम सारी चीजों को कर लेंगे पर अब यह अक्षमता क्यों जाहिर कर रहे है? जनता के अदर अविश्वास का यही प्रधान कारण होता है। आप एक चीज निश्चित कर देते है, और फिर थोड़े दिनों के लिए सो जाते है। उसकी तरफ देखते नही हैं। थोड़े दिनों के बाद जब याद आया तो उसका टाइम बढ़वा दिया। मेरा कहना है कि यही अविश्वास का बहुत बड़ा कारण होता है। मै समझता हूं आपको कठिनाईयां है, इसलिए आपने समय और चाहा। ठीक चाहा। लेकिन कठिनाई पैदा हुई क्यों? अगर आप जानते हैं तो आपको समझाना चाहिए। आप 6 महीने का समय और क्यों बढ़वाना चाहते है इसका उत्तर आप नहीं दे सके सिवाय इसके कि आप ने अपनी अक्षमता जाहिर की, सरकारी मशीनरी की अक्षमता जाहिर की और दूरंदाजी से काम नही किया।

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देता हूं। कल बहस हो रही थी नदियों की। सारी दुनिया में नदियां बरदान साबित हुई हैं और हमारे लिए नदियां अभिशाप जाहिर हो रही हैं। हम सारा काम युद्ध स्तर पर करना चाहते हैं। कितनी ढीली है हमारी सरकार जो हर काम के लिए युद्ध स्तर का नाम लेती है। मैं आप को याद दिला दूं कि 15 साल तक इजराइल में एक दिन भी कैबिनेट हटी नहीं। ताज्जुब होगा कि एक रेस्पांसिबिल मिनिस्टर ही कुर्सी पर बैठा रहा, एक मिनट के लिए भी कैबिनट पदच्युत नहीं हुआ। यह है युद्ध स्तर। एक-एक मिनट की रिपोर्ट आती रही, लड़ाई का सामान कहां पहुंचा, ट्यूब बेल कहां बन रहे हैं, कारखाने कहां लग रहे हैं, सामान क्यों नहीं गया, इस काम में देरी क्यों हो रही है, यह सब खबरें उन को एक-एक मिनट में मिलती रहीं। यह है युद्ध स्तर। यहां आप सोच रहे हैं कि सारी चीजें अपने हाथ में ले लें। आप जिस चीज को भी अपने हाथ में लेते हैं उस के ऊपर ध्यान नहीं देते, सो जाते हैं। जब याद आया तो जाग उठे और प्राइस बढ़ाने की बात कर दी। 1 P.M. केवल इसी बात का एतराज है। आप छः महीने के बजाय साल भर कर लीजिए। अगर आपको कोई बाधा सामने आ रही है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अपनी सरकारी मशीनरी को ठीक कीजिए। इसके कारण से देश का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। अगर थोड़ा-सा नुक्सान पैसे का हो तो यह बहुत गम्भीर बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर मिनिस्ट्री पर जनता का विश्वास नहीं रहता है तो यह गम्भीर बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर विश्वास खो दें, मिनिस्टर विश्वास खो दें, बड़े से बड़े अधिकारी विश्वास खो दें तो क्या आप इसको मजाक समझते हैं? यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इसलिए आप जिस चीज को लीजिए उसको सोच-समझकर अपने हाथ में लीजिए और इस बात को भी देख लीजिए कि क्या आप उस चीज को टाइम के अन्दर पूरा कर सकते हैं? मुझे केवल यही विरोध है, वरना आप छः महीने के बजाय इसकी अवधि साल भर के लिए बढ़ा दीजिए।

SHRI K. N. DHULAP (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to make my observations on the ESSO (Acquisition of Undertakings in India) Amendment Bill, 1974.

At the outset, Sir, I will charge the Ministry with negligence and taking Parliament for granted. Sir, this amending Bill was published on the 29th August, 1974. It was introduced in this House yesterday, the 2nd September, 1974. Today the hon. Minister wants it to be passed by this august House.

Sir, the time envisaged in the original section 13 of the parent Act was 180 days. It was to start from the 13th March, 1974. So approximately now the last date must be 13th September, 1974...

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : 8th September.

SHRI K. N. DHULAP : ...8th September, 1974. Now the Government wants this legislation to be rushed through, and, therefore, I charge this Ministry of negligence. The Government wants this legislation to be rushed through when they come to know that because of the complex nature of the contract to be terminated within 180 days—

contracts for service, supply and sale—they could not complete the finalisation of the issues that were before the Ministry. Sir, it would be in the fitness of things if I asked the hon. Minister to supply this august House how many contracts were there categorywise in relation to sale, service and supply? So three categories are there. How many contracts are already terminated by the Ministry? This is absolutely necessary, because in sub-section (2) of section 13 of the parent Act it has been stated very specifically. The obligation is on he Government to see that the contracts which are not beneficial to the Govt. Company or the Government should be immediately terminated. Section 13(2) of that Act reads like this :

> "The Central Government may, if it is satisfied that any contract referred to in sub-section (1) is unduly onerous or has been entered into in bad faith or is detrimental to the interests of that Government or the Government Company, by order in writing, either terminate such contract or make such alterations or modifications there as it deems fit."

This is obligatory. A statutory provision has already been made in the parent Act that if the financial interest is jeopardised because of those contracts in connection with sales, supply and service, they should be terminated by the Government and even though the word 'may' is used in this sub-section that 'may' means 'shall'. The Government has to see that no financial loss is caused to the Govt. company or to the Government since the Government has taken over the undertaking. So I want to know from the hon. Minister how many contracts have been terminated by the Government as is envisaged by sub-section (2) of section 13 of the original Act. Then we could know why these things have been delayed; then we could know what has come in the way of finalising and terminating all the contracts which were in existence at the time of the taking over of the company by the Government. So this is absolutely necessary. Therefore I would request the hon. Minister to take the House into confidence and give us a little information as to how many contracts have been terminated and within the further period of six months for which extension has been sought whether all the contracts are likely to be fully examined by the Government and those which are detrimental to the interests of the Govt. company or the Goverament will be terminated within that period. The Government should not come to this House again for an extension of the period.

Secondly I would like to make a small point which the Government should take note of. While the negotiations were going on for taking over the ESSO big salaried officers of the Government were there and they ought to have gone through all these contracts at the time of taking over the company. Why they could not have envisaged at that time that this is going to take more time? The officers who are responsible for this should also be taken to task and they should be held responsible for not terminating the contracts within the time as is visualised by the relevant section in the parent Act and thereby causing financial loss to the Govt. company or the Govt.

With these words I have done.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I would like to ask him one question only. Now the officers are very important. What has happened to Mr. A.P. Verma of your Ministry? Where has he gone now? Is it a fact that you have given him a promotion and sent him to a higher position despite the fact that the CBI dossier is full of corruption charges against him? Did you verify from the CBI as to what were the charges and allegations against him some of which have been proved to the satisfaction of the CBI before sending him to the Indo-Burma Corporation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes; the Minister will reply now.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Sir, the Bill before the House is a very simple one.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, only the simpletons will think it a simple one

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : All that is desired to be done is to extend the period from six months to one year. As I have stated, there was a very large number of contracts which the ESSO Company had entered into. These contracts were of two different types; one was long-range contracts which were entered into by the Company with bigger houses and bigger firms. They were long-range contracts extending over long periods.

There were short-term contracts which were entered into by various regions and branches. For instance, a contract has to be entered into with the retail dealer for every pump that is given on contract to somebody else. So, there were thousands and thousands of such contracts. We appointed a committee consisting of officers of the Ministry of Petroleum and Chemicals and the Ministry of Finance. We also appointed a task force consisting of officers of the Ministry of Petroleum and Chemicals, the Finance Ministry and the Ministry of Law. Some of these contracts, we found, were of a complicated nature. They require very detailed scrutiny in each individual case. The long-range contracts are the more important ones. There are a little over a hundred contracts which have to be thoroughly scrutinised. Eighty per cent of the work has been completed. Because these contracts are of a complicated nature, after the 8th of September...

SHRI NIREN GHOSH : What are those complications and what is the nature?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : ..they become binding on us. Therefore, we have come forward with a request that this House may be kind enough to give us a little more time. It would be our endeavour to complete this job as early as possible, but as a measure of abundant precaution we have asked for a period of six months. The other matters which were raised were of a general nature.

SHRI NIREN GHOSH : No, it was specific. What about equalisation of the price of petrol and oil products throughout India?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : These were thoroughly discussed when the main Bill was under discussion. Under the ESSO takeover Bill all these points were fully discussed and I do not think any useful purpose will be served by repeating the reply which my senior colleague has already given.

SHRI BHUPESH GUPTA : My question has not been answered.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to amend the ESSO (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI BHUPESH GUPTA : Now, Sir, it has been said as to why we all oppose this Bill and our opposition continues. I asked him a question to which he should have given a reply. You will see how it is relevant because certain deals with the foreign oil companies have been entered into by some officials, some of whose records are extremely dubious .

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Sir, may I reply to Mr. Bhupesh Gupta?

SHRI NIREN GHOSH : You reply to my equalisation point.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Mr. Bhupesh Gupta wanted to know what has happened to one Mr. Verma. Frankly speaking, I do not know at this moment what job he has been given. I will make enquiries and let him know.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am very glad...

SHRI NIREN GHOSH : He has not replied to my question.

SHRI BHUPESH GUPTA : Ask when you get up.

Sir, he does not know. He should find out. I just give you very little information. Mr. Verma was in your Ministry. Against him there were very serious charges of collusion with foreign interests, and in many of the deals with the foreign oil concerns, he played an important part, with a view to helping the foreign oil concerns and other agencies. And he had been known as a man of such type. The matter has been brought to the notice of the Minister; the matter has been, I believe, brought to the notice of the Prime Minister that this gentleman Mr. A.P. Verma, should not be in any responsible position. Then we came to know about him. As I said, Sir, I know it for a fact. Now, let him inquire it from his own channel by asking Mr. Mirdha. Let him come and say after enquiry that the CBI does not have a heavy dossier about Mr. A.P. Verma. According to my information—and very reliable information,—the CBI dossier about his malpractices, shady deals and corruption is quite a heavy one, and that should be known to the Prime Minister, to the Minister and others concerned. And I am surprised, even so he is getting patronage like certain other people in the Ministry, from the Government.

Now, I think the matter has been brought to the notice of the Government by a number of MPs. Nothing had happened. All that I would like to say in this situation when the Government is taking over something, that it is very important that you eliminate all officials against whom there are serious allegations —allegations, I am saying very carefully— of corruption and collusion, collusion with the foreign oil interests. Over the past several years, the foreign oil interests, ESSO and others, have created a lobby of their own in the Ministry, and it is well known how some of them had been functioning...

SHRI NIREN GHOSH : For twenty years.

SHRI BHUPESH GUPTA : For twenty years or so.

The time has come today, not to go in for this kind of a deal, but to outrightly nationalise these concerns and take them over— ESSO and others—and see that the Oil Ministry is rid of such officers and such other elements—one of them I have mentioned. I hope he will make enquiries and let us know. Anyhow, I demand a thorough scrutiny in the light of the disclosures made in this House and the other information that the Government may have of all those officers who are suspected of having connections with big business including the foreign interest and who are taking advantage and benefit out of them in some way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We adjourn till 2.15 P.M. and we shall take up the discussion on the situation in Bihar.

The House then adjourned for lunch at nineteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

DISCUSSION UNDER RULE 176—*RE* PRESENT SITUATION IN BIHAR

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : On a point of order. I am not opposed to a discussion on Bihar. I do not say that you should rule out the discussion. Since you have admitted it let it take place. But I want to point out a thing for future guidance. Bihar has a State Government. It is not under the President's Rule.... (*Interruption by Shri Rajnarain*) I am not coming in your way. You will have your say. But I would not like you to follow this double standard. When we want a discussion on Maharashtra you deny. When we want a discussion on U.P. you deny. When we want a discussion